भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2658
19 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत केरल को दी गई निधियां

2658. एडवोकेट अद्दूर प्रकाश:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन से अब तक इस योजना के अंतर्गत केरल राज्य को प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का वर्ष - वार ब्यौरा क्या है;

(ख) जारी की गई, उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और इससे कितने मछुआरे लाभान्वित हुए हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान केरल राज्य के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लंबित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके अनुमोदन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क): विगत तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) और वर्तमान वर्ष (2023-24) के दौरान, प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार (पीएमएमएसवाई) ने केरल में मात्स्यिकी विकास हेतु केरल सरकार के विभिन्न मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को 355.33 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ 941.02 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है । पीएमएमएसवाई की शुरुआत से केरल सरकार को स्वीकृत वर्ष-वार परियोजनाओं और केंद्रीय वित्तीय सहायता का विवरण निम्नलिखित है:-

रु/- करोड़ में

वर्ष	**अनुमोदित परियोजनाएं**	**केंद्रीय हिस्सा**
2020-21	113.67	42.32
2021-22	183.37	62.72
2022-23	502.24	207.15
2023-24	141.74	43.14
कुल	**941.02**	**355.33**

(ख): केरल को स्वीकृत 941.02 करोड़ रुपये की कुल परियोजनाओं में से 239.27 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान केरल राज्य सरकार को जारी की गई । केरल सरकार ने राज्य में अनुमोदित मात्स्यिकी विकास गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए 224.27 करोड़ रुपये के व्यय की सूचना दी है और अब तक 144.35 करोड़ रुपये की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है । केरल सरकार ने रिपोर्ट किया है कि पीएमएमएसवाई के तहत लगभग 1,60,302 मछुआरे और मत्स्य-किसान लाभान्वित हुए हैं ।

(ग): 2023-24 के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने केरल सरकार की 141.74 करोड़ रु/- की लागत वाले मात्स्यिकी विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी है । अनुमोदित गतिविधियों में गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति के लिए नई फिश हैचरी की स्थापना, ब्रूड बैंक, गुणवत्तापूर्ण फ़ीड की आपूर्ति के लिए फ़ीड मिलें, इनपुट के साथ फ्रेश वॉटर पॉण्ड, इनपुट के साथ ब्रैकिश वॉटर कल्चर, प्रौद्योगिकी से जुड़ी बायोफ्लॉक इकाइयां और री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) जैसी गतिविधियां, जलाशयों में फिंगरलिंग्स का भंडारण, बाइवाल कल्टिवेशन, ओर्नमेंटल फिश रियरिंग यूनिट्स, डीप सी फिशिंग वेस्सेल्स, निर्यात क्षमता के लिए मौजूदा फिशिंग वेस्सेल्स का उन्नयन, फिशिंग हारबर्स का विकास और आधुनिकीकरण, फिश लैंडिंग सेन्टर्स का विकास, आर्टिफ़िश्यल रीफ़्स की स्थापना, आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, परिवहन वाहन जैसे-रेफ्रिजरेटेड वाहन, इंसुलेटेड वाहन, आइस बॉक्स के साथ मोटरसाइकिल, आइस बॉक्स के साथ थ्री वीलर, लाईव फिश वेंडिंग केंद्र, घरेलू खपत बढ़ाने के लिए फिश कियोस्क, जैव-शौचालय, डीजीज डायगनोस्टिक और क्वालिटी टेस्टिंग मोबाइल लैब/क्लिनिक, और मत्स्यन गतिविधि पर प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान पारंपरिक मछुआरों के परिवारों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता तथा सागर मित्र शामिल हैं

(घ): केरल सरकार का कोई भी प्रस्ताव मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार में अनुमोदन के लिए लंबित नहीं है ।

*****